एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस :
निर्यात लाभ

मार्च 2019
खंड XXXV अंक ।

इस अंक में

1 भारत के श्रम बाजार परिदृश्य पर निर्यातों का प्रभाव
3 विशेष कवरेज : भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर सीआईआई-एक्ज़िम बैंक का 14वां सम्मेलन
5 पंजाब से निर्यात
6 मेक्सिको के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध
7 रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चापरक सत्र
8 गुजरात में पहली बार, एक्ज़िम बाज़ार : हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की अनूठी प्रदर्शनी
9 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
10 तिमाही गतिविधियां
11 एक्ज़िम बैंक का 34वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान
12 एक्ज़िम बैंक की गतिविधियां
13 चुनिंदा देशों का आर्थिक परिदृश्य
14 मुद्रा की प्रवृत्तियां
15 आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था
16 व्यापार और साझेदारी अवसर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

प्रधान कार्यालय :
केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल
कफ़ परेड, मुंबई- 400 005.
टेलीफोन : +91-22-2217 2600
ई-मेल : ccg@eximbankindia.in

भारत के श्रम बाजार परिदृश्य पर निर्यातों का प्रभाव

निर्यात किसी देश के आर्थिक विकास में इंजन का काम करते हैं। क्योंकि निर्यातों से देश के उत्पादकों को न सिर्फ बड़ा बाजार मिलता है, बल्कि कामगारों की क्षमता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कौशल में भी सुधार आता है। अर्थव्यवस्था पर निर्यातों का बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी विकास की तुलना में निर्यात देश के उत्पादकों के लिए अधिक लाभदायक होते हैं और उन्हें आर्थिक स्थायित्व प्रदान करते हैं। हालिया विश्लेषणों में निर्यातों से होने वाले इस लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है, खास तौर पर देश में रोजगारों से इसके संबंध पर विशेष जोर दिया गया है।

भारत जैसे देशों के लिए निर्यातों और रोजगारों में इस तरह के संबंधों का विश्लेषण विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, जहां हमेशा से बढ़ती श्रम शक्ति को रोजगार देने के लिए नए क्षेत्रों की जरूरत है। विश्व बैंक-अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, अब से 2030 तक करीब 100 मिलियन लोग श्रम बाजार में खड़े होंगे। इसमें 54% भारतीय होंगे। अतः भारत को हर साल 5-9 मिलियन रोजगारों का सृजन करना होगा।[1] तथापि, नौकरियों की संख्या ही एकमात्र कठिनाई नहीं है। नौकरियों की गुणवत्ता बढ़ाना और नौकरियों तथा आय के तुलनात्मक रूप से असमान आय वितरण को ठीक करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।

भारत में अनौपचारिक रोजगार का अनुपात करीब 60-92% है और औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र में आय में एक बड़ा अंतर है। आकलनों के अनुसार, 2011 में औपचारिक कामगारों की आय अनौपचारिक कामगारों की तुलना में 3.2 गुना अधिक रही। भारत में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रीय समूहों में अंतर भी काफी अधिक है। उच्च शिक्षा प्राप्त कामगारों की आय प्राथमिक शिक्षा प्राप्त स्तर के कामगारों की तुलना में 5.5 गुना अधिक रही। शहरी कामगारों की आय ग्रामीणों की तुलना में 2.4 गुना अधिक रही और पुरुषों की आय महिलाओं की तुलना में 1.7 गुना अधिक रही।[2]

इसलिए, देश के नीति निर्माताओं के लिए प्राथमिकता अधिक नौकरियों का सृजन करना ही नहीं, बल्कि विभिन्न वर्गों में व्याप्त आय की असमानता को कम करना भी है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) और विश्व बैंक-आईएलओ के हालिया शोध अध्ययन में श्रम बाजार से सकारात्मक परिणाम हासिल करने में निर्यातों के प्रभाव पर जोर दिया गया है। भारत उच्च विकास दर हासिल करने की ओर अग्रसर है। अतः रोजगार की चुनौतियों से निपटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्यातों के प्रभाव का मूल्यांकन करना महत्त्वपूर्ण होगा।

रोजगारों पर भारतीय निर्यातों का प्रभाव

निर्यातों और रोजगार के बीच संबंध स्थापित करने की दिशा में पहला आवश्यक कदम ऐसे विश्वसनीय तंत्र का विकास करना होगा, जिससे एक निश्चित समय के दौरान भारतीय निर्यातों से सृजित होने वाले रोजगारों का आकलन किया जा सके। इस प्रकार के आकलन की जरूरत को महसूस करते हुए, एक्ज़िम बैंक ने भारत में निर्यातों और रोजगारों के बीच संबंधों पर एक शोध अध्ययन किया। इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1999 से 2000 के दौरान कुल निर्यातों (वस्तु और सेवा) से भारत में 34 मिलियन रोजगारों का सृजन हुआ, जो 2012-13 में बढ़कर 62.6 मिलियन हो गए[3] और इसमें 3.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वस्तुतः 2012-13 में भारत में कुल रोजगारों में करीब 14.5% हिस्सा निर्यात क्षेत्र में रोजगारों का रहा।

यद्यपि निर्यातों से रोजगारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई देती है, तथापि प्रति मिलियन यूएस डॉलर के निर्यातों पर रोजगारों की संख्या में गिरावट आई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे- श्रम उत्पादकता में सुधार (जिसका एक मतलब उच्च वेतन भी हो सकता है)। निर्यातों के स्वरूप का अधिक कुशलतापूर्ण और पूंजी प्रधान उत्पादों का होना भी एक अन्य कारण हो सकता है। गिरावट के बावजूद, अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति मिलियन यूएस डॉलर के निर्यातों पर रोजगारों की संख्या अधिक रही। एक्ज़िम बैंक का शोध अध्ययन बताता है कि 2012-13 के दौरान भारत में 1 मिलियन यूएस डॉलर के निर्यातों पर 138 नौकरियां रहीं। जबकि अमेरिका में 2014 के दौरान नौकरियों का यह आंकड़ा 5.2 रहा।

[1] Artuc, Erhan; Lopez-Acevedo, Gladys C.; Robertson, Raymond; Samaan, Daniel. 2019. Exports to Jobs: Boosting the Gains from Trade in South Asia (English). South Asia Development Forum. Washington, D.C.: World Bank Group.

[2] Ibid.

[3] रोजगार संबंधी डाटा एक चुनौती है और अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए वित्तीय वर्ष 2017 में उपलब्ध नवीनतम डाटा वित्तीय वर्ष 2013 का था।

विश्व बैंक-आईएलओ द्वारा किया गया हालिया शोध अध्ययन भी वेतन और अनौपचारिकता को कम करने के संबंध में रोजगारों पर निर्यातों के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि करता है। अध्ययन के अनुसार, भारत के निर्यातों में प्रति कामगार 1500 रुपये की बढ़ोत्तरी से प्रति कामगार के वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि हुई और 12.4 मिलियन अनौपचारिक श्रमिक कम हो गए **(चार्ट 1)**। स्पष्ट है, एक सुदृढ़ निर्यात आधारित विकास रणनीति से भारत के श्रम बाजार में उल्लेखनीय उन्नति हासिल की जा सकती है।

चार्ट 1 : वेतन और अनौपचारिकता पर प्रति कामगार निर्यातों में बढ़ोत्तरी का प्रभाव

प्रति कामगार निर्यातों में वृद्धि के बाद औसत वार्षिक वेतन में परिवर्तन (1999-2011)

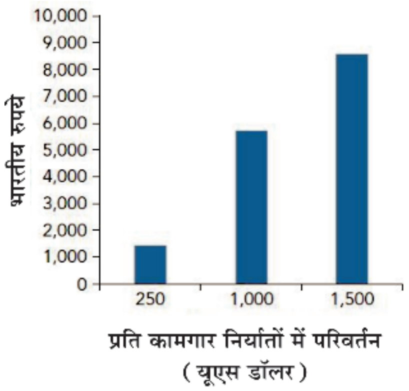

प्रति कामगार निर्यातों में वृद्धि के बाद अनौपचारिकता में परिवर्तन (1999-2011)

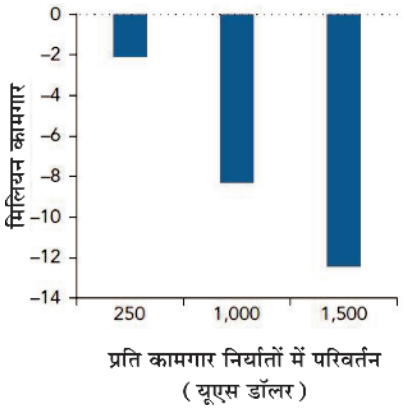

स्रोत : विश्व बैंक-आईएलओ अध्ययन

शोध अध्ययन बताता है कि निर्यात आधारित विकास रणनीति श्रम बाजारों से हासिल किए जाने वाले परिणामों का भी निर्धारण करती है। वर्तमान में, भारत से निर्यातों का स्वरूप पूंजी प्रधान है। अतः यदि किसी तरह का पूंजी प्रधान व्यापार शॉक[1] आता है तो उच्च शिक्षा प्राप्त निपुण कामगारों पर इसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा और निर्यातों में प्रति कामगार 250 यूएस डॉलर की बढ़ोत्तरी से उनकी औसत आय 5,318 रुपये बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर, पूंजी प्रधान निर्यात संकट का कम कुशल कामगारों पर अधिक असर पड़ेगा और प्राथमिक से कम, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कामगारों के वेतन में सबसे अधिक बढ़ोत्तरी होगी।

निर्यात वृद्धि और स्थानीय श्रम बाजार विकास के बीच संबंध भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। 1999-2011 के दौरान, कुछ राज्यों में कामगारों के वेतन में सुधार लाने में निर्यातों की अहम भूमिका रही। सबसे अधिक लगभग 15% वेतन वृद्धि अधिक निर्यातों के चलते पुदुचेरी और झारखंड में हुई। गुजरात और पश्चिम बंगाल से बेहतर निर्यातों की बदौलत वहां करीब 10% की वेतन वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र में कुल वेतन वृद्धि में निर्यातों के चलते हुई वेतन वृद्धि 5% से अधिक रही। जहां तक अनौपचारिकता का संबंध है तो, जिस अवधि के लिए यह अध्ययन किया गया उस अवधि के लिए दिल्ली में अनौपचारिकता के स्तर में आई गिरावट से इसे बेहतर समझा जा सकता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, बेहतर निर्यातों के चलते अनौपचारिकता के स्तर में करीब 40% की गिरावट आई।

निर्यातों और स्थानीय श्रम बाजार के बीच संबंधों का राज्य सरकारों पर नीतिगत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कई नीतियां राज्य स्तर पर ही बनाई जाती हैं और ये नीतियां निर्यात झटकों के प्रभाव को बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। व्यापार सुगमीकरण, मानक व्यवस्था में सुधार और उत्पादन चक्र में और अधिक वैल्यू एडिशन के लिए राज्य सरकारों की और अधिक भागीदारी अपेक्षित है। इससे उत्पादन और निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा और परिणामस्वरूप, राज्यों में बाजार स्थितियों पर सकारात्मक असर दिखाई देगा।

निर्यात वृद्धि में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अंतर-राज्यीय व्यापार परिषद और व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का गठन किया है। ये संस्थाएं व्यापार को सुगम बनाने संबंधी मामलों में संघ और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संस्थागत संवाद के तंत्र के रूप में काम करेंगी। एक्ज़िम बैंक भी राज्यों के लिए निर्यात रणनीति शोधपत्र तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता रहा है, जो राज्य के स्तर पर निर्यात संबंधी नीति निर्माण में सहायक होते हैं। इस क्षेत्र में किए गए शोधों में समावेशी विकास के दृष्टिकोण से भी राज्य स्तर पर इस प्रकार की निर्यात रणनीतियों की जरूरत पर बल दिया गया है।

निष्कर्ष

निर्यातों में वृद्धि, रोजगार वृद्धि का रामबाण इलाज नहीं है। तथापि, हालिया शोध अध्ययन में नौकरियों की संख्या और उनकी प्रकृति में निर्यात वृद्धि के योगदान को स्थापित किया गया है। अतः एक सुदृढ़ निर्यात रणनीति में श्रम बाजार में विद्यमान अंतरों और देश में लंबे समय से मौजूद अनौपचारिकता को कम करने की क्षमता होती है। इस क्षेत्र में हालिया शोध अध्ययन के प्रसार से अन्य राज्य सरकारें भी केवल आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपने-अपने राज्यों में नौकरियों की संख्या और गुणवत्ता जैसे मसलों से निपटने के लिहाज से भी अपनी निर्यात रणनीतियां और नीतियां बनाने के लिए प्रेरित होंगी।

केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां और उपाय अपनाने की जरूरत है, जिनसे निर्यातों से होने वाले लाभ को फैलाने में मदद मिले। इसमें बुनियादी ढाँचे, बेहतर कनेक्टिविटी और मुक्त व्यापार में निवेश करते हुए, लोगों से निर्यात को जोड़ने और उसे बढ़ाने जैसे उपाय शामिल हैं। निर्यात रणनीति में, श्रम बाजार विनियमों में सुधारों के जरिए, वस्तु निर्यातों में महिलाओं की भागीदारी और कामगारों की गतिशीलता को बढ़ाते हुए उत्पादन में आने वाली विकृतियों को हटाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अधिक पूंजी प्रधान वृद्धि के मार्ग पर चलना अपरिहार्य है और देश के इस प्रकार के परिवर्तन की ओर अग्रसर होने के साथ ही प्रशिक्षण के प्रयास बढ़ाने की भी जरूरत होगी। यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण होगा कि वेतन में असमानताएं न बढ़ें और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

विशेष कवरेज : भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर सीआईआईआई-एक्ज़िम बैंक का 14वां सम्मेलन

भारत-अफ्रीका के बीच परियोजना साझेदारी पर सीआईआईआई-एक्ज़िम बैंक का 14वां सम्मेलन 17 से 19 मार्च, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर इसका आयोजन किया। 2005 में अपनी शुरुआत के बाद से ही यह वार्षिक सम्मेलन भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी को मजबूत करने तथा आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने वाले एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में उभरा है। अफ्रीकी बाजारों में भारतीय परियोजनाओं को बढ़ाने का मार्ग सुगम बनाने में भी इस सम्मेलन का अहम योगदान रहा है। इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के उच्चाधिकारियों और पेशेवरों के बढ़ते समन्वय से भारत-अफ्रीका के बीच आर्थिक गतविधियां भी बढ़ी हैं। सम्मेलन में दोनों क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण गणमान्य हस्तियां हिस्सा लेती हैं, जिनकी सक्रियता से दोनों क्षेत्रों के बीच साझेदारी का पुल और मजबूत हुआ है।

14वें सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने किया। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच 60 अरब यूएस डॉलर का वर्तमान व्यापार हमारी क्षमता से बहुत कम है। हमें यह व्यापार बढ़ाने और इसमें विविधता लाने की जरूरत है। उन्होंने भारत और अफ्रीका के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता करने का सुझाव दिया, जो अपनी तरह की एक अनूठी पहल होगी और अफ्रीका की जरूरतों के अनुसार, उसके लिए लाभप्रद भी होगी। उन्होंने कहा कि भारत-अफ्रीका भागीदारी को और बेहतर बनाने के लिए भारत तैयार है, जिसका प्रथम लाभ अफ्रीका को मिलेगा और इससे वैश्विक बाजार में अफ्रीका की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

अफ्रीकी महाद्वीप में 50 से ज्यादा देश शामिल हैं और यह एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है, जहां बड़े पैमाने पर विविधतापूर्ण अवसर विद्यमान हैं। अवसरों में विद्यमान इस विविधता को देखते हुए इस पूरे महाद्वीप के लिए कोई एक रणनीति या कोई एक दृष्टिकोण अपनाना व्यवहार्य नहीं होगा। इस क्षेत्र में अपर्याप्त बुनियादी ढांचागत सुविधाएं (भौतिक, वित्तीय डिजिटल और मानव संसाधन), वित्त तक सीमित पहुंच और विनियामक परिवेश में चुनौतियों जैसी विभिन्न बाधाओं को हाइलाइट किया गया है। इन बाधाओं को दूर करने और सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी, नवोन्मेषी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, भारतीय निवेशों का विशाखन, खाद्य सुरक्षा में साझेदारी, ऊर्जा समाधान, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, संपर्क तथा अन्य कई उपायों पर काम किया गया है।

घाना के माननीय उपराष्ट्रपति डॉ. महामुदू बावूमिया; गिनी के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. इब्राहिमा कसोरी फोफाना, लेसोथो के माननीय उप-प्रधानमंत्री श्री मोनियाने मोलेलेकी इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तीनों गणमान्य व्यक्तियों ने मौजूदा भारत-अफ्रीका साझेदारी और अपने-अपने देशों तथा महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बात की।

14वें सीआईआईआई-एक्ज़िम बैंक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में, 17 मार्च, 2019 को एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना और कांगो की माननीय राजदूत सुश्री मोस्सी न्यामाले रोज़ेटी द्वारा 83.11 मिलियन यूएस डॉलर की तीन ऋण-व्यवस्थाओंसंबंधी करारों का आदान-प्रदानकिया गया। ये ऋण-व्यवस्थाएं कांगो के करावा, बंदका और लुसांबो नामक तीन प्रांतों में कुल 35 मेगावाट की क्षमता वाली 3 सौर फोटोवोल्टिक विद्युत-परियोजनाओं की स्थापना के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

समापन सत्र के दौरान वाणिज्य सचिव, भारत सरकार, श्री अनूप वधावन ने कहा कि अफ्रीकी संघ के एजेंडा 2063 में उल्लिखित अनुसार, अफ्रीका को सतत विकास और समावेशी उन्नति के प्रयासों तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भारत तत्परता के साथ सहयोग करने की भावना से काम करता है।

यह सम्मेलन व्यापार, निवेश और विकासात्मक गतिविधियां बढ़ाने के बहुआयामी उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत भारतीय तथा अफ्रीकी व्यावसायियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच एक पुल की भूमिका में रहा। सम्मेलन में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और इनकी चुनौतियों, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, क्षमता निर्माण, कृषि विकास और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई।

14वें सीआईआईआई-एक्ज़िम सम्मेलन में एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन का विमोचन

भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर नई दिल्ली में 17 मार्च, 2019 को आयोजित 14वें सीआईआईआई-एक्ज़िम बैंक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में, भारत-सैडेक व्यापार और निवेश संबंधः संभावनाओं का विस्तार शीर्षक वाले एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन का विमोचन किया गया। इसका विमोचन माननीय केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा विभिन्न गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान गणमान्य अतिथियों में घाना के माननीय उपराष्ट्रपति डॉ. महामुदू बावूमिया; गिनी के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. इब्राहिमा कसोरी फोफाना, लेसोथो के माननीय उप-प्रधानमंत्री श्री मोनियाने मोलेलेकी, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार में सचिव डॉ. अनूप वधावन, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष श्री राकेश भारती मित्तल और सीआईआई के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बनर्जी शामिल रहे। एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन में दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (सैडेक) क्षेत्र में वर्तमान व्यापार और निवेश परिदृश्य और भारतीय व्यवसायों के लिए विद्यमान अवसरों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में सैडेक के अंतः क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार तथा विदेशी निवेशों के रुझानों को हाइलाइट किया गया है। साथ ही व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए रणनीति भी सुझाई गई है।

सैडेक क्षेत्र में आने वाले देश अफ्रीकी महाद्वीप का अभिन्न अंग हैं, जिनका 2017 में अफ्रीका के कुल भौगोलिक क्षेत्र, जीडीपी और आबादी में लगभग एक तिहाई हिस्सा था। 2017 में अफ्रीका के सकल घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) में अफ्रीका के प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार संगठनों में, सैडेक का सबसे ज्यादा योगदान रहा। विश्व व्यापार संगठन

(डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, अफ्रीकी क्षेत्रीय व्यापार करार (आरटीए) में सैडेक का मूल्य की दृष्टि से पहला स्थान है और 2017 में कुल अफ्रीकी निर्यातों में इसका 37.3 प्रतिशत हिस्सा रहा है।

अन्य विकासशील देशों को भारत के बढ़ते वैश्विक व्यापार के चलते सैडेक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है। पिछले दस वर्षों में सैडेक देशों के साथ भारत का कुल व्यापार वर्ष 2008 में 13.7 अरब यूएस डॉलर से लगभग दोगुना बढ़कर 2017 में 25.5 अरब यूएस डॉलर हो गया है। भारत के कुल व्यापार में सैडेक का हिस्सा 2008 के 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 42.4 प्रतिशत हो गया।

सैडेक के व्यापारिक पार्टनर के रूप में भारत के बढ़ते महत्व का आकलन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि सैडेक के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2008 में 2.9 प्रतिशत से लगभग दोगुनी बढ़कर 2017 में 6.4 प्रतिशत हो गई।

सैडेक को भारत के निर्यात में खनिज ईंधन और दवा उत्पादों का दबदबा बना हुआ है। वर्ष 2017 में सैडेक को भारत के कुल निर्यात में इनका 46.7 प्रतिशत हिस्सा रहा। हालांकि खनिज ईंधन की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई, किन्तु पिछले दस वर्षों के दौरान दवा उत्पादों की संख्या में दोगुनी से अधिक वृद्धि हो गई है। दक्षिण अफ्रीका सैडेक में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जिसका 2017 में भारत के कुल निर्यात का लगभग 44.9 प्रतिशत हिस्सा रहा है। सैडेक में अन्य प्रमुख निर्यात बाजार तंजानिया, मोजाम्बिक तथा मॉरीशस हैं। भारत के वैश्विक आयातों में सैडेक का हिस्सा 2008 के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 3.7 प्रतिशत हो गया। सैडेक से भारत के आयातों में प्रमुखतया खनिज ईंधन, तेल और इसके उत्पाद तथा मोती और कीमती रत्न शामिल रहे और 2017 में कुल आयातों का 78 प्रतिशत इन्हीं उत्पादों के लिए रहा। भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ा आयात स्रोत है। इसके बाद अंगोला, बोत्सवाना, तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया का स्थान आता है।

इस अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि यद्यपि 2008 में एफटीए की स्थापना के बाद सैडेक का व्यापार काफी ज्यादा बढ़ा है, तथापि सैडेक के क्षेत्रीय और समग्र व्यापार को बढ़ाने की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। मुख्य रणनीतियों में अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाना, उत्पाद एवं बाजार विविधता, नॉन-टैरिफ बैरियर्स (एन टी बी) में कमी तथा व्यापार के लिए अन्य बाधाओं और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का विकास शामिल है।

संक्षिप्त विवरण : देश के उत्तरी राज्यों में से एक, पंजाब को 'देश की खाद्य टोकरी' के नाम से भी जाना जाता है। यह परंपरागत रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य रहा है। 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर पंजाब के जीएसडीपी में 2013-14 के 3 ट्रिलियन रुपये से 2017-18 में 3.7 ट्रिलियन रुपये की धीमी, लेकिन निरंतर बढ़ोत्तरी दर्ज की गई और 5.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि के चलते रही। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पंजाब का योगदान 2013-14 के 3.1% से गिरकर 2017-18 में 2.9% रह गया।

निर्यात परिदृश्य : पंजाब से निर्यातों में भी गिरावट आई। पंजाब से निर्यात 2017-18 में 5.8 अरब यूएस डॉलर का रहा, जो 2013-14 में 7.1 अरब यूएस डॉलर का था। इस अवधि के दौरान इसमें 4.4% की ऋणात्मक एएजीआर दर्ज की गई। 2017-18 में देश के कुल निर्यातों में 1.95% हिस्से के साथ निर्यात रैंकिंग सूची में पंजाब 13वें स्थान पर रहा।

उत्पाद विश्लेषण : पंजाब से निर्यातित प्रमुख वस्तुओं की बात की जाए तो, 2017-18 में राज्य से कुल निर्यातों में 67.1% हिस्सा शीर्ष 10 वस्तुओं का ही रहा।

चार्ट 1 : 2017-18 में पंजाब से निर्यातित प्रमुख वस्तुएं

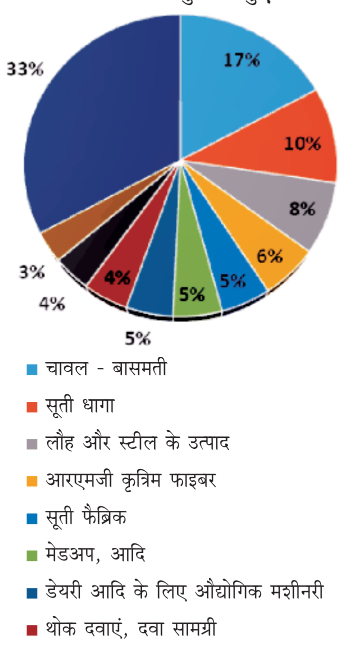

कुल निर्यात : 5.8 अरब यूएस डॉलर

स्रोत : ट्रेड मैप, आईटीसी जेनेवा

एचएस-6 डिजिट वाले उत्पादों के निर्यात की बात करें तो, 2017-18 में राज्य से कुल निर्यातों में 44.4% हिस्सा शीर्ष 10 निर्यातित उत्पादों का रहा। सबसे अधिक निर्यातित उत्पाद बिना पॉलिश वाले या ग्लेज्ड (एचएस कोड - 100630), सेमी-मिल्ड या पूर्ण-मिल्ड चावल रहे। इनका निर्यात 2013-14 के 1715.8 मिलियन यूएस डॉलर से गिरकर इस अवधि के दौरान 1064.3 मिलियन यूएस डॉलर का रहा और इसमें (-) 9.7% की एएजीआर दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 में पंजाब से निर्यात में इस उत्पाद का हिस्सा घटकर 18.4% रह गया, जो वर्ष 2013-14 में 24.3% था। वर्ष 2017-18 में भारत से निर्यातित इस उत्पाद का लगभग 15% हिस्सा पंजाब से रहा। एचएस कोड 100630 के निर्यातों में गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक प्रमुख कारण इस अवधि के दौरान ईरान को निर्यात में आई गिरावट रहा।

वर्ष 2017-18 में दूसरा सबसे अधिक निर्यातित उत्पाद गोजातीय पशुओं का बोनलेस फ्रोजन मांस (एचएस कोड - 02023) रहा। इसका निर्यात 2013-14 के 364.5 मिलियन यूएस डॉलर से गिरकर 2017-18 में 271.9 मिलियन यूएस डॉलर का रह गया। हालांकि यह 2016-17 में पांच वर्षों के न्यूनतम स्तर 97.1 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा और इसमें 2013-14 से 2017-18 के दौरान 18.7% की एएजीआर दर्ज की गई। इस एएजीआर में प्रमुख योगदान 2017-18 के दौरान हुई वृद्धि का रहा। 2017-18 में वियतनाम को निर्यात इस वृद्धि का प्रमुख कारण था। 2013-14 में वियतनाम को 77.8 मिलियन यूएस डॉलर के निर्यात के साथ 21.4% निर्यात रहा, जो 2017-18 में दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 52.7% हो गया।

देश विश्लेषण : पंजाब से किन क्षेत्रों को कितना निर्यात किया गया, इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 2013-14 में पंजाब के कुल निर्यातों में 58.5% योगदान तो शीर्ष 10 आयातकों का ही रहा था। 2017-18 में शीर्ष 10 आयातकों का योगदान घटकर 54.5% हो गया, जो निर्यात स्थलों के विशाखन की ओर संकेत करता है। 2017-18 में पंजाब से आयात करने वालों में प्रमुख रूप से यूएसए (11.4%), यूएई (10.4%), ईरान (6.4%), बांग्लादेश (5.6%) और सऊदी अरब (5%) शामिल रहे।

पंजाब में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) : एफडीआई मार्केट्स डाटाबेस के अनुसार, 2008 से 2017 के दौरान भारत में कुल परियोजनाओं में से 1% परियोजनाएं पंजाब में आईं और विदेशी मुद्रा विनिमय (ईएफसी) का 1.4% पंजाब में रहा। इस अवधि के दौरान, पंजाब में 60 कंपनियों द्वारा 81 परियोजनाएं लगाई गईं, जिनसे करीब 26,800 नौकरियों का सृजन हुआ। इन परियोजनाओं में आई विदेशी मुद्रा 5.9 अरब यूएस डॉलर की रही अर्थात औसतन 75.5 मिलियन यूएस डॉलर प्रति परियोजना।

जहां तक कैपेक्स निवेश के लिए परियोजनाओं की संख्या का सवाल है तो पंजाब में सबसे ज्यादा 30 परियोजनाएं अमेरिका की रहीं, जो 2008 से 2017 के दौरान राज्य में लगने वाली कुल परियोजनाओं की एक-तिहाई रहीं। 2008 से 2017 के दौरान, पंजाब में करीब 1.8 अरब यूएस डॉलर का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा विनिमय यूके से रहा, जो इस अवधि के दौरान राज्य के कुल विदेशी मुद्रा विनिमय के 30.4% के समतुल्य रहा। पंजाब में कुल विदेशी मुद्रा विनिमय का 96% शीर्ष 10 देशों से रहा। इसमें भी 58% योगदान अकेले यूके और यूएस से ही रहा।

यह विदेशी मुद्रा विनिमय सबसे अधिक रियल एस्टेट क्षेत्र में रहा। इस क्षेत्र में 2008 से 2017 के दौरान 1556.8 मिलियन यूएस डॉलर का विदेशी मुद्रा विनिमय रहा, कुल विदेशी मुद्रा विनिमय में जिसका योगदान 4.5% रहा। वस्तुतः, इस अवधि के दौरान राज्य में कुल विदेशी मुद्रा विनिमय का 25% अकेले रियल एस्टेट क्षेत्र में ही रहा। इसके बाद कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र का स्थान रहा, जिसमें 953.3 मिलियन यूएस डॉलर का विदेशी मुद्रा विनिमय रहा, जो इस क्षेत्र में भारत के कुल विदेशी मुद्रा विनिमय का 2.6% रहा।

सारांश : यह देखा गया है कि पंजाब की तुलना में लगभग एक समान भौगोलिक बाधाओं का सामना करने वाले बंदरगाह विहीन राज्य उत्तर प्रदेश (4.7%), हरियाणा (4.5%) और राजस्थान (2.3%) से वर्ष 2017-18 में निर्यातों में योगदान पंजाब की अपेक्षा अधिक रहा। निर्यातों में योगदान में सामने आया यह अंतर पंजाब की विविधतापूर्ण औद्योगिक स्थिति और मजबूत उत्पादन नेटवर्क इस कमी को पूरा करने की क्षमता रखता है।

मेक्सिको के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध

मेक्सिको लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका नॉमिनल जीडीपी 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। भारत-मेक्सिको के द्विपक्षीय संबंध बीते कुछ वर्षों से प्रगतिशील रूप से मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं तथा चर्चाएं जारी हैं। दोनों देशों के बीच 2007-08 में एक विशेष साझेदारी की शुरुआत हुई थी।

भारत और मेक्सिको के बीच द्विपक्षीय संवाद के कई तंत्र हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर निवेश, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में करार और एमओयू हैं। प्रमुख संस्थागत संवाद तंत्रों में व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग पर द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह, द्विपक्षीय संयुक्त आयोग, तथा निवेश संवर्धन एवं संरक्षण, दोहरे कराधान बचाव, प्रत्यर्पण, सीमा शुल्क संबंधी मामलों में प्रशासनिक सहयोग, वायु सेवाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, परंपरागत औषधि संवर्धन, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदि के लिए विभिन्न करार और एमओयू शामिल हैं।

मेक्सिको के साथ भारत के अच्छे वाणिज्यिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2011 के 3.5 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2018 में 8.8 अरब यूएस डॉलर हो गया। भारत का निर्यात जहां 2011 के 1.3 अरब यूएस डॉलर की तुलना में 2018 में लगभग तीन गुना बढ़कर 3.8 अरब यूएस डॉलर का हो गया था, वहीं निर्यातों में अभी इसी अवधि के दौरान लगभग दोगुनी वृद्धि हुई थी। 2011 में भारत का निर्यात 2.2 अरब यूएस डॉलर का था, जो 2018 में 5 अरब यूएस डॉलर का हो गया था। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में मेक्सिको 2018 में भारत के लिए सबसे बड़ा आयातक देश रहा और 2018 में इस क्षेत्र से दूसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत भी रहा।

वर्ष 2018 के दौरान, मेक्सिको को सबसे अधिक निर्यातित मदों में परिवहन वाहन शामिल रहे। भारत से मेक्सिको को कुल निर्यातित मदों का कुल 44.6% हिस्सा परिवहन वाहनों का रहा। भारत से 2018 में मेक्सिको को निर्यातित अन्य प्रमुख उत्पादों में जैविक रसायन (8.9%), एल्यूमीनियम और इसकी वस्तुएं (6.9%), मशीनरी और उपकरण (5.3%) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स (4.9%) शामिल रहे। वहीं, 2018 में मेक्सिको से भारत द्वारा आयातित प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन और तेल शामिल रहे, जिनका मेक्सिको से भारत द्वारा कुल आयात का 74.7% हिस्सा रहा। मेक्सिको से अन्य प्रमुख आयातित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स (11.8%), मशीनरी और उपकरण (3.5%), परिवहन वाहन (2.3%) और टैनिंग तथा डाई एक्सट्रैक्ट (1.7%) शामिल रहे।

मेक्सिको लैटिन अमेरिका क्षेत्र से भारत को एफडीआई का प्रमुख स्रोत रहा है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2008 के दौरान मेक्सिको ने भारत में 132.9 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया। नेमाक, मेताल्सा, मेक्सिकेम, ट्रेमेक, ग्रेट फूड्स एंड बेवरेजेज़, रुरपंपेन, सिनेपोलिस और किडज़ानिया जैसी अग्रणी मेक्सिकन कंपनियों ने हाल के दिनों में भारत में निवेश किया है। मेक्सिकन आईटी कंपनी सॉफ्टेक भारत में सेवा प्रदाता के रूप में उपस्थिति दर्ज कराने वाली अपने क्षेत्र की पहली लैटिन अमेरिकी कंपनी बन गई है। हाल ही में बिंबो ग्रुप ने भारत में निवेश करने की घोषणा की है। अप्रैल 1996 से जनवरी 2019 के दौरान मेक्सिको को भारत का जावक एफडीआई 156.1 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। आईटी / सॉफ्टवेयर में भारत की अधिकांश कंपनियां (टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एनआईआईटी, बिड़लासॉफ्ट, एचसीएल, ऐप्टेक, हेक्सावेयर, पटनी, टेक महिंद्रा आदि) और फार्मास्युटिकल कंपनियां (क्लैरिस लाइफ साइंसेज, वॉकहार्ट, सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज, टोरेंट फार्मास्युटिकल्स आदि) ने मेक्सिको की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और बड़े बाजार तथा निवेश अनुकूल नीतियों का फायदा उठाते हुए मेक्सिको में संयुक्त उद्यम स्थापित कर लिए हैं। ओवीएल ने मेक्सिको सिटी में अपना एक कार्यालय भी स्थापित किया है। भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते दूसरे देशों से कच्चा तेल आयात करने पर विचार कर रहा है, ऐसे में मेक्सिको इस क्षेत्र में भारत का अच्छा साझेदार बन सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच पहले से अच्छे संबंध और बेहतर होंगे।

मेक्सिको के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार (अरब यूएस डॉलर)

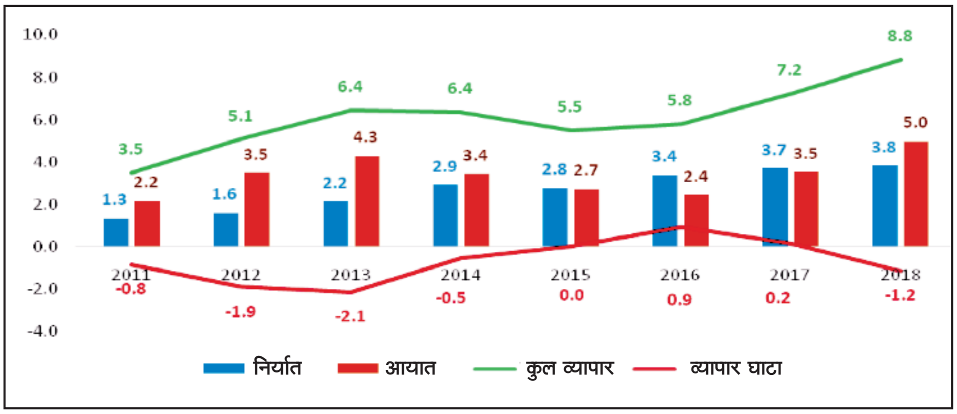

स्रोत : आईटीसी ट्रेडमैप और एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

पृष्ठभूमि : भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मिलकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र तथा यूरोप और ओशियानिया क्षेत्रों के देशों के साथ रणनीतिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर 3 चर्चापरक सेमिनारों का आयोजन किया। ये सेमिनार फरवरी और मार्च के दौरान किए गए। इन सेमिनारों का आयोजन इन क्षेत्रों में मौजूद व्यापार की संभावनाओं को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए उक्त क्षेत्रों के देशों के राजदूतों से चर्चा को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया था। हर सेमिनार में एक्ज़िम बैंक ने ऐसे उत्पादों के विवरण देते हुए विस्तृत प्रस्तुतियां दीं, जिनमें व्यापार की काफी संभावनाएं हैं। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए रणनीतियां भी सुझाईं। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु इन चर्चाओं में विशेष रूप से उपस्थित रहे और उक्त क्षेत्रों के देशों को परस्पर लाभ के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

भारत-अफ्रीका रणनीतिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए संभावनाएं : अफ्रीका के लिए भारत चौथे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है। अफ्रीका और भारत दोनों ही एक-दूसरे के बाजारों में अच्छी पैठ रखते हैं। हालांकि, भारत के आयातों में अफ्रीका का हिस्सा 7.9% है, लेकिन अफ्रीका के आयातों में भारत का हिस्सा 4.5% के साथ काफी कम है। एक्ज़िम बैंक द्वारा दी गई प्रस्तुति में 42 अरब यूएस डॉलर की ऐसी व्यापार संभावनाओं का उल्लेख किया गया, जिन्हें अभी तक भुनाया नहीं गया है। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए अन्य के साथ-साथ प्रमुख रणनीतियां निम्नलिखित हैं :

- बाजार तक पहुंच को आसान बनाना और मुक्त व्यापार करारों की संभावनाएं तलाशना;
- व्यापार और निवेश में सुधार लाने के लिए नीतिगत विकल्पों और समाधानों को चिह्नित करते हुए व्यापार बढ़ाने के लिए वैल्यू चेन लिंकेज स्थापित करना;
- नियामकीय बाधाओं को कम करते हुए परियोजना निर्यातों को बढ़ाना, श्रमशक्ति की आवाजाही आदि में सुधार लाना; और
- स्वास्थ्य सेवा और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास के लिए परस्पर सहयोग।

भारत व लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र (लैक) के बीच रणनीतिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावना : भारत 2017 में लैक के लिए 11वें सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा। 2008 में यह 24वें स्थान पर था। लेकिन हालिया प्रगति के बावजूद, लैक-भारत का व्यापार 2012-13 में 41 अरब यूएस डॉलर के अपने उच्चतम स्तर से कम ही है। भारत के लिए लैक बाजार में विस्तार की अनेक संभावनाएं हैं, क्योंकि लैक के आयातों में भारत का हिस्सा 1.4% ही है, जो वैश्विक निर्यातों में भारत के 1.7% से भी कम है। भारत और लैक के बीच 15.4 अरब यूएस डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की ऐसी संभावनाएं हैं, जिन्हें अभी तक भुनाया नहीं गया है। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए अन्य के साथ-साथ प्रमुख रणनीतियां निम्नलिखित हैं :

- अन्य के साथ-साथ ऑटोमोटिव, फार्मास्युटिकल्स, कृषि-व्यवसाय, एयरक्राफ्ट, आईटी और आईटी आधारित सेवाओं जैसे क्षेत्रों में एफडीआई से विकसित हुई नई उत्पादन मूल्य श्रृंखलाओं का उभरना;
- विशेष रूप से पेट्रोलियम वैल्यू चेन लिंकेज को बढ़ावा देते हुए ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग;
- विशेष रूप से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के जरिए क्षमता निर्माण और नॉलेज शेयरिंग;
- भारत सरकार के ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के जरिए लैक क्षेत्र में बुनियादी विकास को सहयोग देना;
- सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना।

यूरोप और ओशियानिया के साथ भारत के रणनीतिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए संभावनाएं : भारत के व्यापार में यूरोप और ओशियानिया दोनों का उल्लेखनीय योगदान है। भारत ऐसी कई शीर्ष वस्तुओं का प्रमुख वैश्विक निर्यातक है, जो यूरोप और ओशियानिया दोनों द्वारा ही आयात की जाती हैं। वस्तुतः यूरोप के लिए भारत छठे सबसे बड़े अतिरिक्त-क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है। तथापि, यूरोप के कुछ हिस्सों के बाजारों में भारत की अच्छी पैठ है, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में मार्केट शेयर बढ़ाने की जरूरत है और इस क्षेत्र के साथ 90.6 अरब यूएस डॉलर के व्यापार की संभावनाएं आंकी गई हैं, जिन्हें अभी तक भुनाया नहीं गया है। भारत और ओशियानिया के बीच भी 6 अरब यूएस डॉलर के व्यापार की संभावनाएं हैं। द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए अन्य के साथ-साथ प्रमुख रणनीतियां निम्नलिखित हैं :

- ब्रॉड-बेस्ड व्यापार एवं निवेश करार/यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ वार्ताओं में तेजी लाकर और गैर-टैरिफ उपायों के चलते निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं को मिलकर सुलझाते हुए यूरोप के बाजारों तक पहुंच बढ़ाना;
- माल, सेवाओं, निवेश और संबंधित मामलों में व्यापार जैसे विषयों को कवर करने वाले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सेसा) में शीघ्रता लाना;
- निवेश आधारित वैल्यू चेन लिंकेज स्थापित करना;
- अक्षय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अक्षय ऊर्जा में नवोन्मेष के लिए आर एंड डी सहयोग जैसे क्षेत्रों में यूरोप के साथ मिलकर काम करना;
- ओशियानिया के साथ मिलकर काम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा हासिल करना।

भारत-अफ्रीका रणनीतिक आर्थिक सहयोग

भारत-लैक रणनीतिक आर्थिक सहयोग

यूरोप और ओशियानिया के देशों के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग

गुजरात में पहली बार, एक्ज़िम बाज़ार : हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की अनूठी प्रदर्शनी

एक्ज़िम बैंक देशभर में ग्रासरूट उद्यमों और शिल्पकारों को सहयोग प्रदान करता रहा है। बैंक यह सहयोग उत्पाद विकास कार्यशालाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए ही नहीं, बल्कि शिल्पकारों और उद्यमियों के उत्पादों को स्थानीय बाजारों के साथ-साथ विदेशी बाजारों में पहुंचाने में मदद के जरिए भी प्रदान करता रहा है। साथ ही बैंक विभिन्न उद्यमियों को व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में हिस्सा लेकर अपने उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने के लिए भी सहयोग प्रदान करता रहा है। अपने इन प्रयासों को बढ़ाते हुए एक्ज़िम बैंक ने सितंबर 2017 में एक्ज़िम बाज़ार नाम से एक पहल की थी। एक्ज़िम बाज़ार हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की अनूठी प्रदर्शनी है, जहां शिल्पकारों की पहुंच सीधे ग्राहकों तक होती है। इस क्रम में तीसरा एक्ज़िम बाज़ार 04-06 जनवरी, 2019 तक अहमदाबाद हाट में आयोजित किया गया।

एक्ज़िम बाज़ार में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर सहित 25 राज्यों के 55 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी की और अपने-अपने राज्यों की समृद्धि कलात्मक परंपराओं का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रदर्शनी के दौरान कश्मीरी कढ़ाई वाले टेक्सटाइल, पश्मीना ऊन, ढोकरा कला, सांझी पेंटिंग, टेराकोटा और ब्लैक पॉटरी, चेन्नापटना खिलौने, मिनिएचर, फड़ और पिछवाई पेंटिंग, एप्लीक और कढ़ाई किए हुए टेक्सटाइल्स तथा गारमेंट, जूट बैग और मैट, पंजाबी जूती, फुटवेयर, वारंगल कालीन, इकत टेक्सटाइल, ऑर्गैनिक शहद, लेदर कठपुतली, पैर और मुंह से बनाई गई पेंटिंग, पैठणी साड़ी, घास से बुनी टोकरी, सेरामिक पॉटरी, मधुबनी और पट्टचित्र पेंटिंग आदि की बिक्री हुई। इस प्रदर्शनी में 8000 से अधिक लोग आए। प्रदर्शनी के दौरान लगभग 50 लाख रुपये की बिक्री हुई और कई दस्तकारों को आगामी बल्क ऑर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी मिले।

एक्ज़िम बैंक अपनी ग्रासरूट पहलों और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए ग्रासरूट स्तर के उद्यमों तथा विशेष रूप से निर्यात की संभावनाओं वाली नवोन्मेषी तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्हें हर प्रकार (वित्तीय / सलाहकारी) की सहायता प्रदान करता रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे दस्तकारों, उत्पादक समूहों, क्लस्टरों, छोटे उद्यमों और गैर सरकारी संगठनों को मदद करना है, जो देश की समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति को वास्तव में संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किन्तु ग्रासरूट स्तर पर वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और उन्हें उनके उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसे उद्यमियों के उत्पादों को निर्यात के जरिए उन्हें उचित मूल्य दिलवाना प्राथमिकता है। साथ ही बैंक सूक्ष्म भारतीय उद्यमों की परिचालनात्मक क्षमता को बढ़ाते हुए उनके उत्पादों में बेहतर वैल्यू एडिशन और विस्तृत बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद करता है और इस प्रकार निर्यात क्षमता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस हेतु बैंक उन उद्यमों के लिए कौशल विकास, उत्पाद विकास जैसे उपायों के साथ-साथ निर्यात प्रमाणीकरण हासिल करने में भी सहायता प्रदान करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए : grid@eximbankindia.in

अहमदाबाद हाट में एक्ज़िम बाज़ार

फेल्ट क्राफ्ट

फड़ चित्रकारी

फुलकारी

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मध्यम उद्यमों पर विशेष बल के साथ भावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है। ये ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातक समुदाय को जोखिम और दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं, जो उन्हें नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने और मौजूदा विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने में मदद करती हैं। एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है।

हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। बैंक द्वारा अब तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 24.28 अरब यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 246 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

एक्ज़िम बैंक ने जनवरी-मार्च 2019 के दौरान भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित सात ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए :

(I) मोज़ाम्बिक सरकार को 38 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था हैंडपंपों के साथ 1600 बोरवेलों और 8 छोटी जल प्रणालियों के निर्माण के लिए प्रदान की गई है। इस ऋण-व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा मोज़ाम्बिक सरकार को भारत सरकार की ओर से अब तक 772.44 मिलियन यूएस डॉलर की 14 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। मोज़ाम्बिक सरकार को प्रदत्त इन ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत मोज़ाम्बिक में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं, पानी की बोरिंग तकनीक तथा संबंधित उपकरण हस्तांतरित करने, आईटी पार्क परियोजना, चावल-गेहूं-मक्का का उत्पादन बढ़ाने, सोलर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र लगाने, टिका, बूज़ी तथा नोवा सोफाला के बीच सड़क मरम्मत और 900 घरों के निर्माण तथा लोकोमोटिव, रेलवे कोच और वैगन सहित रॉलिंग स्टॉक की खरीद संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं।

(ii) मालदीव सरकार को 800 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था मालदीव में विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई है। इस ऋण-व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा मालदीव सरकार को भारत सरकार की ओर से अब तक कुल 880 मिलियन यूएस डॉलर की तीन ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इन ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए मालदीव सरकार को विभिन्न बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए सहयोग प्रदान किया गया है।

(iii) कांगो सरकार को कुल 83.11 मिलियन यूएस डॉलर की तीन ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गईं। ये ऋण-व्यवस्थाएं कांगो के करावा, बंदका और लुसांबो नामक तीन प्रांतों में कुल 35 मेगावाट की क्षमता वाली 3 सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं। उक्त तीनों ऋण-व्यवस्थाओं सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा कांगो सरकार को भारत सरकार की ओर से अब तक कुल 578.05 मिलियन यूएस डॉलर की 10 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इन ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए कांगो सरकार को जलविद्युत परियोजनाओं, पावर ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं, सीमेंट संयंत्र, हैंड पंप और सबमर्सिबल पंप लगाने संबंधी परियोजनाओं और सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहयोग प्रदान किया गया है।

(iv) उज्बेकिस्तान सरकार को 200 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था उज्बेकिस्तान में आवासन और सामाजिक बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई है। यह उज्बेकिस्तान को भारत सरकार के सहयोग से एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की गई पहली ऋण-व्यवस्था है।

(v) पापुआ न्यू गिनी सरकार को 100 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था सड़क और बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई है। यह पापुआ न्यू गिनी को भारत सरकार के सहयोग से एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की गई पहली ऋण-व्यवस्था है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

श्री नदीम पंजेतन
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
ऑफिस ब्लॉक, टावर 1, 7वीं मंजिल
एड्जेसेंट रिंग रोड, किदवई नगर (पूर्व)
नई दिल्ली - 110 023
टेलीफोन : (011) 24607700
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

सफलता की कहानी : वियतनाम : वियतनाम सरकार को भारत सरकार के सहयोग से एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की गई 19.50 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत बिन बो ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए 9.30 मिलियन यूएस डॉलर की परियोजना नवंबर 2018 में पूरी हो गई। इस ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन से बाढ़ के पानी को नदियों में मोड़ा जा सकेगा। इससे इस क्षेत्र में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी।

सफलता की कहानी : श्रीलंका : श्रीलंका रेलवे को नवंबर 2018 में 58.04 मिलियन यूएस डॉलर की परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक छह डीजल मल्टीपल यूनिट (डीएमयू) की आपूर्ति की गई है। ये डीएमयू आधुनिक ड्राइवर-सह-गार्ड केबिन और अत्याधुनिक इंटीरियर से लैस हैं। यह परियोजना श्रीलंका सरकार को भारत सरकार के सहयोग से एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की गई 382.37 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत कवर की गई है।

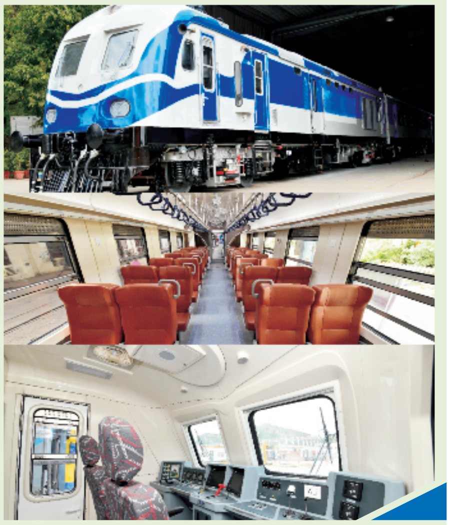

एक्ज़िम बैंक ने 3.875% प्रतिवर्ष की कूपन दर पर 5 वर्ष के लिए जुटाए 500 मिलियन यूएस डॉलर

एक्ज़िम बैंक ने 05 मार्च, 2019 को 500 मिलियन यूएस डॉलर का 5 वर्षीय रेग-एस बॉन्ड निर्गम (इश्यू) सफलतापूर्वक जारी किया। निर्गम को 117 से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों से कुल 1.7 अरब यूएस डॉलर का अभिदान मिला, जो निर्गम की राशि से 3.4 गुना ज्यादा है। निर्गम से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल दीर्घावधि ऋणों और ऋण-व्यवस्थाओं के माध्यम से भारतीय परियोजना निर्यातों तथा विदेश में निवेश को सहायता के लिए किया जाएगा।

यह संव्यवहार CT5 + 140 बीपीएस के उचित मूल्य पर किया गया था, जो CT5 + 165 बीपीएस क्षेत्र के प्रारंभिक मूल्य के अंदर था। यह 25 बीपीएस की महत्त्वपूर्ण टाइटनिंग और नए शून्य निर्गम प्रीमियम को प्रदर्शित करता है। भौगोलिक वितरण की दृष्टि से, इसका वितरण एशिया में 87% तथा यूरोप एवं यूएस के ऑफशोर में 13% रहा। निर्गम के लिए एचएसबीसी बैंक तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जॉइंट लीड मैनेजर और बुक रनर के रूप में काम किया। एक्ज़िम बैंक को मूडीज द्वारा बीएए2 (स्थिर) तथा फिच द्वारा बीबीबी- (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है, जो भारत सरकार की रेटिंग के समतुल्य है।

बॉन्ड निर्गम को उच्च गुणवत्ता वाले निवेशक वर्ग को वितरित किया गया जिसमें से 44% फंड एवं असेट मैनेजर्स को, 29% बैंकों को तथा 20% बीमा एवं संप्रभु धन निधि तथा 7% निजी बैंकों को वितरित किए गए।

एक्ज़िम बैंक ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत लैटिन अमेरिका क्षेत्र में सूरीनाम सरकार को 15 मिलियन यूएस डॉलर का क्रेता ऋण प्रदान किया

एक्ज़िम बैंक ने लैटिन अमेरिका क्षेत्र में सूरीनाम सरकार को सूरीनाम के 10 क्षेत्रों में 19 वर्टिकल एक्सिस पंपों के डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति, निरीक्षण तथा स्थापना हेतु 15 मिलियन यूएस डॉलर का दूसरा क्रेता ऋण प्रदान किया। इस परियोजना का निष्पादन किर्लोस्कर ब्रदर्स लि., इंडिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में बीसी-एनईआईए करार पर पारामारिबो, सूरीनाम में हस्ताक्षर हुए। इस करार पर सूरीनाम के माननीय वित्त मंत्री गिलमोर होफड्राड तथा एक्ज़िम बैंक की ओर से अमेरिका-वाशिंगटन डीसी प्रतिनिधि कार्यालय के निवासी प्रतिनिधि श्री शैलेश प्रसाद, उप महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सूरीनाम के माननीय कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालन मंत्री श्री लेखराम सोर्डजन तथा सूरीनाम में भारत के राजदूत श्री महेन्दर सिंह कन्याल उपस्थित रहे।

लैटिन अमेरिका क्षेत्र में बीसी-एनईआईए के अंतर्गत यह दूसरी सुविधा दी गई है। इससे न केवल भारत के निर्यातों को लैक क्षेत्र में बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीय निर्यातकों को और भी क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर मिलेगा। बीसी-एनईआईए बैंक की एक ऐसी विशिष्ट वित्तपोषण योजना है, जो भारतीय निर्यातकों को मध्यम या दीर्घावधि के लिए ऋण प्राप्त करने का सुरक्षित एवं दायित्व रहित वित्तपोषण विकल्प प्रदान करती है। यह सुविधा निर्यातकों को पारंपरिक बाजारों के साथ-साथ विकासशील देशों के नए बाजारों में पहुंचने में भी मदद करती है।

एक्ज़िम बैंक को मिलेगी 6000 करोड़ रुपए की पूँजी, अधिकृत पूँजी दोगुनी कर 20,000 करोड़ रुपए की

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) में 6000 करोड़ रुपए की पूँजी डालने के लिए भारत सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी करने के फैसले पर मुहर लगाई। यह इक्विटी वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4500 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1500 करोड़ रुपए की दो किस्तों में डाली जाएगी। एक्ज़िम बैंक के इस पुनर्पूंजीकरण से भारतीय निर्यातों को सहयोग प्रदान करने की बैंक की क्षमता बढ़ेगी और बैंक को पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने एक्ज़िम बैंक की अधिकृत पूँजी भी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।

एक्ज़िम बैंक भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। बैंक भारतीय कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विश्लेषण और शोध आधारित विभिन्न उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराता है। बैंक अपने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के जरिए भारतीय निर्यातक कंपनियों को उनके वैश्वीकरण के प्रयासों में भी सहयोग प्रदान करता है।

इंडिया आईएनएक्स में लिस्ट हुआ एक्ज़िम बैंक का 500 मिलियन यूएस डॉलर का बॉन्ड

एक्ज़िम बैंक की स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान माला की शुरुआत 1986 में बैंक का परिचालन शुरू होने के उपलक्ष्य में की गई थी। यह व्याख्यान अंतरराष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक व्यापार, निवेश प्रवाह और संबंधित आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवीनतम रुझानों पर विमर्श को प्रोत्साहन देने का बैंक का एक प्रयास है और प्रबुद्धजनों के विचारों पर चिंतन-मनन करने का एक मंच है। बीते कुछ वर्षों में एक्ज़िम बैंक की इस वार्षिक व्याख्यान माला ने मुंबई के सार्वजनिक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रथम उप प्रबंध निदेशक डॉ. जॉन लिप्स्की; अंकटाड के महासचिव श्री सुपाचई पानिचपाकडी; विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष प्रोय निकोलस स्टर्न; लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रोफेसर लॉर्ड मेघनाद देसाई; न्यूजीलैंड के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री जेम्स ब्लॉगर; यूएनडीपी के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर डॉ. केमल डर्विस; कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स और लॉ के प्रोफेसर जगदीश भगवती; चाइना सोसायटी ऑफ वर्ल्ड इकनॉमिक्स के अध्यक्ष प्रो. यू योंगदिंग और अफ्रीकी विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड कबेरुका जैसी हस्तियों द्वारा यह व्याख्यान प्रस्तुत किया जा चुका है।

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने मुंबई में 9 जनवरी, 2019 को एक्ज़िम बैंक का 34वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान प्रस्तुत किया। प्रोफेसर बनर्जी एमआईटी में अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब के सह-संस्थापक और निदेशक भी हैं। साथ ही वह भारत के योजना आयोग में मानद परामर्शदाता भी रहे हैं। उनके इस स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान का विषय ''सामाजिक नीति की पुनर्रचना'' था।

प्रो. बनर्जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि भारत का सामाजिक नीति का ढांचा ऐसे समय में बनाया गया था, जब भारत की गिनती दुनिया के गरीब देशों में की जाती थी। लेकिन आज भारत को इन नीतियों को नए सिरे से रचने की जरूरत है। उन्होंने सामाजिक नीति के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और शहरीकरण जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम करने की जरूरत है। साथ ही इनके समाधान भी सुझाए।

प्रोफेसर बनर्जी ने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि हालांकि पिछले वर्षों के मुकाबले आज भारत में स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, लेकिन उन बच्चों का ज्ञान उनकी कक्षा के स्तर का नहीं है और इस स्थिति में कोई प्रगति नहीं हो रही है। उहोंने इस पर भी प्रकाश डाला कि जीवन प्रत्याशा बढ़ने, बचपन में कुपोषण और एंटीबायोटिक्स के प्रति बढ़ती प्रतिरोधात्मकता के चलते हमारा देश किसी गैर-संक्रामक बीमारी वाले संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारा देश वृद्धिशील रूप से तृतीयक चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जबकि हमें प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, ताकि बीमारी की जांच पहले ही हो सके और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अधिक विश्वसनीय परामर्श दे सकें। उन्होंने इसके संभावित समाधान भी सुझाए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को चिह्नित करना, उनकी क्षमताओं के लगातार परीक्षणों और प्रमाणन के जरिए उनका विनियमन करना इसका संभावित समाधान हो सकता है।

प्रोफेसर बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारे देश में उतने रोजगारों का सृजन नहीं हो पा रहा है, जितने रोजगारों की जरूरत है। उद्योगपतियों में यह आम धारणा बनती जा रही है कि उन्हें वैसे कुशल मानव संसाधन नहीं मिल रहे हैं,जैसा वे चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े सुधारों के बिना इसकी संभावना भी काफी कम दिखाई देती है कि निजी क्षेत्र में उतने रोजगारों का सृजन हो पाएगा, जितने भारतीय युवाओं को आने वाले समय में चाहिए। उन्होंने भारत के विनिर्माण क्षेत्र की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया जो सिर्फ निर्यातों तक सीमित न हों और इन क्षेत्रों में बेहतर परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तथा इन्हें भूमि और पर्यावरण संबंधी मंजूरियां आसानी से मिल पाएं। देश में रोजगारों के सृजन के लिए यह एक समाधान हो सकता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के संबंध में उन्होंने सुझाया कि कोई भी योजना जनता के एक बड़े तबके को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। उन्होंने एक नया सामाजिक ढांचा बनाने का भी सुझाव दिया, जहां सरकार यह स्वीकार करे कि वह विशिष्ट समूहों को उनकी क्षमता के अनुसार सहायता प्रदान करेगी और ऐसे समूहों को चिह्नित करने की एक व्यवस्था बनाए। यह व्यवस्था किसानों के स्थान और उत्पादन के आधार पर बनाई जा सकती है। क्योंकि व्यक्तिगत पहचान के मुकाबले भौगोलिक पहचान अधिक बेहतर होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई गन्ना उत्पादक ब्लॉक है और उसमें यदि किसी गन्ना नीति के चलते गन्ना उत्पादन कम लाभप्रद रहता है, तो गन्ना किसानों इसका हर्जाना दिया जाए। इस हर्जाने के लिए उन्होंने सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीय निकाय बनाने का सुझाव दिया।

प्रोफेसर बनर्जी ने इसका भी विशेष उल्लेख किया कि हमारे देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। कई छोटे-छोटे कस्बे शहरों में तब्दील हो रहे हैं और बहुत से छोटे-छोटे गांव कस्बों का आकार ले रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने अच्छे बुनियादी ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शहरों को एक संघीय ढांचे में काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने संसाधन जुटाने के लिए रणनीतिक रूप से भूमि बेचने और रियल एस्टेट टैक्स वसूलने की जरूरत पर भी जोर दिया।

एक्ज़िम बैंक ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के आंवला उत्पादकों को सहयोग प्रदान किया

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) भारत की परंपरागत कला और शिल्प को सहेजने और शिल्पकारों को नियमित आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्य से देशभर के ग्रासरूट उद्यमों और शिल्पकारों को उत्पाद एवं डिजाइन विकास तथा पैकेजिंग के लिए सहयोग प्रदान करता रहा है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के परंपरागत कार्यों में लगे उद्यमियों को भी सहयोग प्रदान करता रहा है। बैंक ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के जरिए नई पीढ़ी के शिल्पकारों को अपनी परंपरागत शिल्प कलाओं को सीखने और व्यवसाय का मॉडल खड़ा करने के लिए प्रेरित करते हुए विभिन्न शिल्प कलाओं को भारत तथा विदेशों के अनेक बाजारों में स्थापित करने में उनका सहयोग किया है।

एक्ज़िम बैंक ने सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (CTED), लखनऊ के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गूंदे गांव में उत्पाद विकास कार्यशाला का आयोजन किया। देश में सबसे अधिक आंवला यूपी के प्रतापगढ़ जिले में ही होता है। उत्पाद विकास कार्यशाला का उद्देश्य आंवला उत्पादों की बड़ी रेंज के बारे में जागरूकता पैदा करना था। साथ ही कार्यशाला के दौरान आंवला चाय, आंवला बिस्किट और आंवला एनर्जी ड्रिंक जैसे कुछ नए उत्पाद भी लॉन्च किए गए और उनके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आंवला प्रसंस्करण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को वैज्ञानिकों और खाद्य प्रसंस्करण विशेषज्ञों से चर्चा करने का अवसर मिला। साथ ही प्रतिभागियों को अन्य विनिर्माताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही नवोन्मेषी स्वदेशी प्रसंस्करण तकनीक के बारे में भी जानकारी मिली। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं और तकनीकों का प्रयोग दिखाने का असर यह हुआ कि कुछ आंवला उत्पादक आंवला उद्यमी बनने के लिए प्रेरित हुए और उनमें आत्मविश्वास जगा।

एक्ज़िम बैंक अपनी ग्रासरूट पहलों और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए ग्रासरूट स्तर के उद्यमों तथा विशेष रूप से निर्यात की संभावनाओं वाली नवोन्मेषी तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्हें हर प्रकार (वित्तीय / सलाहकारी) का सहयोग प्रदान करता रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे दस्तकारों, उत्पादक समूहों, क्लस्टरों, छोटे उद्यमों और गैर सरकारी संगठनों को मदद करना है, जो देश की समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति को वास्तव में संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किन्तु ग्रासरूट स्तर पर वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और उन्हें उनके उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसे उद्यमियों के उत्पादों को निर्यात के जरिए उन्हें उचित मूल्य दिलवाना बैंक की प्राथमिकता है। साथ ही बैंक सूक्ष्म भारतीय उद्यमों की परिचालनात्मक क्षमता को बढ़ाते हुए उनके उत्पादों में बेहतर वैल्यू एडिशन और विस्तृत बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद करता है और इस प्रकार निर्यात क्षमता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस हेतु बैंक उन उद्यमों के लिए कौशल विकास, उत्पाद विकास जैसे उपायों के साथ-साथ निर्यात प्रमाणीकरण हासिल करने में भी सहयोग प्रदान करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए : grid@eximbankindia.in

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र की गतिविधियां

एक्ज़िम बैंक ने फिओ के साथ मिलकर 21 फरवरी, 2019 को फरीदाबाद में एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का विषय ''अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उद्यमिता को प्रोत्साहन'' विषय पर रखा गया। इस सेमिनार में हरियाणा से 70 से अधिक निर्यातकों ने हिस्सा लिया। ''केरल से निर्यात : चुनिंदा क्षेत्रों पर फोकस'' विषय पर 13 मार्च, 2019 को कोच्चि में फिओ के साथ मिलकर ही एक अन्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में केरल के 100 से ज्यादा निर्यातकों ने हिस्सा लिया। सेमिनार के दौरान सीमा शुल्क विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), रबर बोर्ड और मसाला बोर्ड से वक्ताओं को आमंत्रित किया गया। एक्ज़िम बैंक ने सेमिनार से इतर ''भारतीय पर्यटन उद्योग : वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवसरों की तलाश'' शीर्षक वाले अपने प्रकाशन का विमोचन किया। एक्ज़िम बैंक ने फिओ के साथ मिलकर पंजाब से निर्यातों पर 25 मार्च, 2019 को लुधियाना में भी एक सेमिनार का आयोजन किया।

भारत की ऋण-व्यवस्थाओं और सौर परियोजनाओं पर 11 फरवरी, 2019 को चेन्नै में बिजनेस आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ मिलकर किया गया। इसके अतिरिक्त, एक्ज़िम बैंक ने ऋण-व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार के आइडियाज दिशानिर्देशों और आगामी परियोजना अवसरों पर विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर भारतीय निर्यातकों के लिए कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नै में चर्चापरक सत्र का भी आयोजन किया।

अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले एक्ज़िम बैंक के आगामी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए देखिए : www.eximbankindia.in/upcoming-events.

एक्ज़िम बैंक का पूर्वानुमान, वित्तीय वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा भारत का वस्तु निर्यात और गत वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में 5.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा भारत का गैर-तेल निर्यात

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2019 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले भारत के कुल वस्तु निर्यातों में 7.7 प्रतिशत (80.6 अरब यूएस डॉलर से 86.8 अरब यूएस डॉलर की वृद्धि) तथा गैर-तेल निर्यातों में 5.1 प्रतिशत (70.0 अरब यूएस डॉलर से 73.6 अरब यूएस डॉलर) की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान एक्ज़िम बैंक के एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) मॉडल पर आधारित है, जिसमें निरंतर वृद्धि देखी गई है। भारत के कुल वस्तु निर्यातों और गैर-तेल निर्यातों में वृद्धि का पूर्वानुमान हर तिमाही आधार पर संबंधित तिमाही के लिए जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा और इस मॉडल में भी निरंतर सुधार का प्रयास किया जाता रहेगा। अप्रैल-जून 2019 तिमाही के लिए भारत के निर्यातों में वृद्धि का अगला पूर्वानुमान जून 2019 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा।

इस मॉडल तथा इससे प्राप्त पूर्वानुमान संबंधी परिणामों की समीक्षा विशेषज्ञों की एक स्थाई तकनीकी समिति द्वारा की गई है। इस समिति के सदस्यों में प्रोफेसर सैकत सिन्हा रॉय, प्रोफेसर एवं संयोजक, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, अर्थशास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता; डॉ. सरत धल, निदेशक, अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई; प्रोफेसर एन.आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फायनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली तथा प्रोफेसर सी. वीरामणि, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई शामिल हैं।

अपने शोध प्रयासों की कड़ी में एक्ज़िम बैंक का भारत के निर्यातों का तिमाही आधार पर ट्रैक रखने तथा वृद्धि में पूर्वानुमान के लिए एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) तैयार करने हेतु विकसित यह इन-हाउस मॉडल है। यह इंडेक्स देश के निर्यातों पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न बाह्य एवं घरेलू कारकों को ध्यान में रखते हुए कुल वस्तु एवं गैर-तेल निर्यातों में तिमाही आधार पर वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में विकसित किया गया है।

डिस्क्लेमर : *उपर्युक्त परिणाम नीति निर्माताओं, शोधार्थियों और निर्यातकों के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। ये पूर्वानुमान एक्ज़िम बैंक के शोध एवं विश्लेषण समूह द्वारा निकाले गए हैं। इसे एक्ज़िम बैंक की राय न माना जाए। उपर्युक्त तिमाही के लिए ईएलआई से निकाली गई गैर-तेल निर्यातों में वृद्धि का आंकड़ा, कुछ विकसित और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा हाल ही में अपनाए गए संरक्षणवादी उपायों के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितताओं के अनुसार बदल सकता है। हालिया उपलब्ध डाटा में सुधार तथा अग्रिम पूर्वानुमान पद्धति को अपनाते हुए तथा विभिन्न तिमाहियों में प्राप्त टिप्पणियों, सुझावों और फीडबैक को शामिल करते हुए इस मॉडल में लगातार सुधार किया जाता रहेगा। वास्तविक निर्यात डाटा भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई के आंकड़ों से लिया गया है।*

बोलिविया

बोलिविया का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2017 के 4.2 प्रतिशत से गिरकर 2018 में 4.1 प्रतिशत रहा। 2019-23 के दौरान, औसत वास्तविक डीजीपी वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। निजी खपत बढ़ने और बुनियादी ढांचे तथा हाइड्रोकार्बन्स में निवेश के चलते यह वृद्धि बनी रहेगी। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2018 में 2.3 प्रतिशत रही थी, जिसके 2019 में बढ़कर 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी होने का अनुमान, देश में चुनावों से पहले मांग का दबाव बढ़ने के चलते है। सेंट्रल बैंक ऑफ बोलिविया (बीसीबी) द्वारा 2019 के अंत में होने वाले अगले राष्ट्रपति चुनावों तक बोलिवियाई बोलिवियानो का मूल्य 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 6.91 तक बनाए रखने की उम्मीद है। बीसीबी द्वारा बोलिवियानो में धीरे-धीरे अवमूल्यन के कयास लगाए जा रहे हैं और अनुमान के मुताबिक, 2022 के अंत तक बोलिवियानो की विनिमय दर 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 7.4 बोलिवियानो तक होने के आसार हैं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ने से आयात बढ़ने के चलते 2019 में चालू खाता घाटा भी 2018 के 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 6.6 प्रतिशत होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त, वस्तु कीमतों को नियंत्रण में रखने से निर्यात राजस्व भी अवरुद्ध होगा और इससे व्यापार घाटा बढ़ेगा।

इक्वेटोरियल गिनी

इक्वेटोरियल गिनी की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, जिसके 2023 तक जारी रहने के आसार हैं। 2018 के दौरान, वास्तविक जीडीपी में 7 प्रतिशत की गिरावट आई। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें गिरने और अंतरराष्ट्रीय भंडारण और सरकारी जमाओं के अनुरूप बफर के अभाव के चलते इस देश को मंदी का सामना करना पड़ा। मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति न होने से मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। इक्वेटोरियल गिनी की मुद्रा सीएफए फ्रैंक है, जो 1 यूरो के मुकाबले 655 सीएफए रही। इसलिए यूरो-डॉलर में उतार-चढ़ाव के साथ इसमें भी उतार-चढ़ाव आता रहता है। निर्यात-आयात दोनों में गिरावट आने के चलते चालू खाता घाटा 2018 में जीडीपी के 3.1 प्रतिशत से घटकर 2023 में जीडीपी का 0.3 प्रतिशत रहने के आसार हैं। देश से सबसे अधिक निर्यात होने वाले उत्पादों में कच्चा तेल अग्रणी है और कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में कमी आने और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के चलते देश के निर्यातों में भी कमी आने की आशंका है। वित्तीय बाधाओं के चलते आयातों में भी गिरावट आने की आशंका है। व्यवसाय परिवेश में कुछ सुधार आने और कुछ विदेशी निवेशों के चलते 2020 से गैर-तेल अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आने की उम्मीद है।

ओमान

प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ने और निर्यातों में वृद्धि होने के चलते तथा ओपेक करार के समाप्त होने के बाद ओमान की आर्थिक वृद्धि दर 2018 की 2.4 प्रतिशत के मुकाबले 2019 में 2.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 2019 में 2.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो 2018 में 0.9 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति में यह बढ़ोत्तरी एक्साइज टैक्स और वैट लागू करने के चलते हुई। हालांकि, तेल और गैर-तेल वस्तु कीमतों में वैश्विक गिरावट के चलते वैट का प्रभाव आंशिक रूप से नगण्य हो जाने की उम्मीद है। ओमान की मुद्रा 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 0.385 ओमान रियाल है, जिस पर 2014 के मध्य में तेल कीमतों में भारी गिरावट आने के चलते अवमूल्यन का खतरा है और इससे ओमान के निर्यात मूल्य में भी कमी आई है। तथापि, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान आर्थिक स्थिरता के लिए अपनी मुद्रा के मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। ओमान को निर्यातों से होने वाली आय में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हाइड्रोकार्बन्स निर्यातों का है और 2014-16 में तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद 2018 में तेल की कीमतों में आए सुधार के चलते देश की बाहरी स्थिति मजबूत हुई है। चूंकि तेल की गिरती कीमतें हाइड्रोकार्बन्स के निर्यातों पर नकारात्मक असर डालती हैं, इसलिए 2019 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाटा बढ़ने के आसार हैं। 2018 में चालू खाता घाटा जीडीपी का 6.2 प्रतिशत था, जो 2019 में बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो सकता है।

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2019 में 2.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष 2.7 प्रतिशत था। दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था विदेशों से मांग पर निर्भर है। खास तौर पर दक्षिण कोरियाई सेमिकंडक्टर डिवाइसों के लिए भारी मांग है। लेकिन दक्षिण कोरिया के इस क्षेत्र पर कम से कम 2020 तक अमेरिका-चीन के व्यापार युद्ध का नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। इससे स्थानीय निर्यातक भारत सहित आसियान देशों के ऐसे उभरते बाजारों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिन्हें अभी तक भुनाया नहीं जा सका है। निजी खपत आर्थिक वृद्धि का प्रमुख कारक बना रहेगा। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 2019 के दौरान बढ़कर 1.6 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो 2018 में 1.5 प्रतिशत दर्ज की गई थी। दक्षिण कोरिया तेल और एलएनजी के दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक है और तेल की वैश्विक कीमतों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव के चलते इसकी अर्थव्यवस्था के संवेदनशील बने रहने के आसार हैं। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा इस साल दरों में कोई परिवर्तन किए जाने की उम्मीद नहीं है, इसलिए दक्षिण कोरियाई वोन का 2019 में अधिमूल्यन होने की उम्मीद है और 1 यूएस डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य औसतन 1,089 वोन रहने के आसार हैं। चालू खाता अधिशेष 2018 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत था, जिसके 2019 में घटकर जीडीपी का 4.6 प्रतिशत रहने की आशंका है।

मुद्रा की प्रवृत्तियां

ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग

यूरोपीय संघ के नेतृत्व और ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रेक्ज़िट को छह महीने के लिए टालने की घोषणा के बाद पाउंड की अस्थिरता कुछ कम हो गई।

इससे नो-डील ब्रेक्ज़िट का जोखिम भी कम हुआ, जिससे पाउंड के और अधिक अस्थिर होने की आशंका थी। लेकिन मई में आम चुनाव के बाद ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व के बदल जाने की संभावना के बीच यह आशंका भी कम हो गई। साथ ही, यूरोपीय संघ से कब और कैसे अलग होना है, इसे लेकर ब्रिटिश राजनेताओं में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बीच ब्रिटेन में कई महीनों से जारी अनिश्चितता के बढ़ने की संभावना से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को संभावित खतरा भी कम हुआ है।

यूरोपीय संघ के नेतृत्व और ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रेक्ज़िट को छह महीने के लिए टालने की घोषणा के बाद करंसी डेरिवेटिव बाजार में ब्रिटिश पाउंड में अस्थिरता की आशंकाएं भी पिछले एक साल में सबसे कम रहीं।

स्टर्लिंग में आई अस्थिरता का असर व्यापक रहा, जिससे इसके मूल्य में गिरावट आई और यह जनवरी 2018 से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। निकट भविष्य में ब्रेक्ज़िट संबंधी किसी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम के न होने की आशंका इस गिरावट की प्रमुख वजह रही। रोजगार के अच्छे आंकड़े भी धीमे व्यापार में कोई जान नहीं फूंक पाए।

ऑफिस फॉर नैशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, बोनस सहित कुल आय फरवरी तक तीन महीनों में 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। यह मध्य 2008 से संयुक्त रूप से उच्चतम दर रही।

पाउंड का मूल्य डॉलर के मुकाबले 1.3070 के निचले स्तर पर रहा और यूरो के मुकाबले 0.25 प्रतिशत कमजोर होकर 86.49 पेंस रहा।

निवेशक सर्वेक्षणों में भी अनिश्चितता को हाइलाइट किया गया। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच द्वारा किए गए एक मासिक सर्वेक्षण में पाया गया कि यूके स्टॉक्स में अधिकांश निवेशकों के रुचि न दिखाने के चलते ग्लोबल मनी मैनजरों के बीच यूके सबसे कम पसंद किया गया क्षेत्र रहा।

ब्राजीलियाई रियाल

वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के कार्यभार संभालने के बाद, रायटर्स पोल में बताए अनुसार, पेंशन सुधारों को लेकर उभरे राजनीतिक तनाव के चलते ब्राजीलियाई रियाल पहली बार कमजोर हुआ।

ब्राजीलियाई मुद्रा के लिए 1-4 अप्रैल तक 26 विश्लेषकों के सर्वे का माध्य अनुमान 12 महीने में 3.70 प्रति डॉलर रहा। यह प्रोजेक्शन 4 अप्रैल को इसके मूल्य से 4.7 प्रतिशत मजबूत है, जो तीन महीने में इसमें हुए सुधार को प्रदर्शित करता है।

4ई कंसल्टैंसी के अर्थशास्त्री ब्रुनो लावेरी के अनुसार, पेंशन सुधारों को तभी मंजूरी मिलेगी जब राजस्व पर पड़ने वाले इनके प्रभाव को कम किया जाएगा। उनके अनुसार, रियाल एक साल में 4.05 प्रति डॉलर रहेगा, जो सबसे आशावादी विचारों में से एक है।

ब्राजील के रिटायरमेंट सिस्टम में बदलावों को अन्य मंत्रियों और संसद सदस्यों का समर्थन न मिलने पर अर्थव्यवस्था मंत्री पाउलो गेदेस द्वारा इस्तीफा देने की धमकी दे दी गई थी। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान बाजार को संभालने के लिए अधिकारियों को सामने आना पड़ा।

आशा है कि अनुकूल बाहरी स्थितियों के चलते ब्राजील की घरेलू समस्याएं हल हो सकेंगी। मोनेक्स यूरोप में एफएक्स विश्लेषक सिमोन हार्वे के अनुसार, वे ब्राजीलियाई रियाल के उभरते बाजारों के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय (ईएमएफएक्स) को लेकर आशान्वित हैं। क्योंकि उभरते बाजारों में वैश्विक विपरीत परिस्थितियां कम हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिका में दरों में संभावित कटौती के चलते यूएस डॉलर में भी सेल ऑफ हो सकता है। उधर, चीन में उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए चीनी प्राधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना है। बाहरी मांग बढ़ना ब्राजील के व्यापार संतुलन के लिए अच्छा है।

चीनी युआन

यूएस डॉलर के मुकाबले चीनी युआन में आई मजबूती अभी जारी रहने की उम्मीद है और आने वाले साल में मौजूदा स्तर से कुछ और मजबूत होने की उम्मीद है। क्योंकि रॉयटर्स पोल के अनुसार, यूएस-चीन व्यापार युद्ध डील कमजोर घरेलू आर्थिक वृद्धि की चिंता को ऑफसेट कर देता है।

वर्ष 2018 में डॉलर के मुकाबले 6 प्रतिशत की गिरावट के बाद, विश्लेषक जनवरी में चीनी युआन का मूल्य 7 प्रति डॉलर होने का आकलन कर रहे थे, लेकिन युआन इस साल डॉलर के मुकाबले 2.5 प्रतिशत मजबूत हुआ।

चीनी युआन में यह मजबूती वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापार वार्ताओं में हुई प्रगति और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा ऊंची मिड-पॉइंट रेफरेंस दरें निर्धारित करने के चलते आई।

अमेरिका और चीन, दोनों पक्षों द्वारा वार्ता में प्रगति बताए जाने के बाद बाजार विश्लेषकों ने अपना ध्यान वाशिंगटन में की जाने वाली नवीनतम वार्ताओं पर केंद्रित कर दिया।

यूएस डॉलर के बदलते मिजाज के चलते भी युआन में मजबूती की उम्मीदें बन रही हैं। मंदी के संकेतों के बीच फेडरल रिजर्व द्वारा पिछले महीने ब्याज दरें बढ़ाने के पूर्वानुमानों पर पानी फेरने के बाद डॉलर पर संकट के बादल मंडरा गए। इससे उभरते बाजारों की मुद्राओं को पिछले साल आई गिरावट से उबरने में मदद मिल सकती है।

पोल के पूर्वानुमान जनवरी में किए गए सर्वे से पूरी तरह एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। जनवरी में अधिकांश विश्लेषक साल के मध्य तक युआन के 7 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचने का आकलन कर रहे थे।

नवीनतम पोल में, अधिकांश विश्लेषक युआन को लेकर आशान्वित रहे। आर्थिक मंदी और नीतिगत नरमी के चलते केवल 4 प्रतिक्रियाओं में आगामी वर्ष में युआन के 7 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचने की बात कही गई है।

वस्तु व्यापार

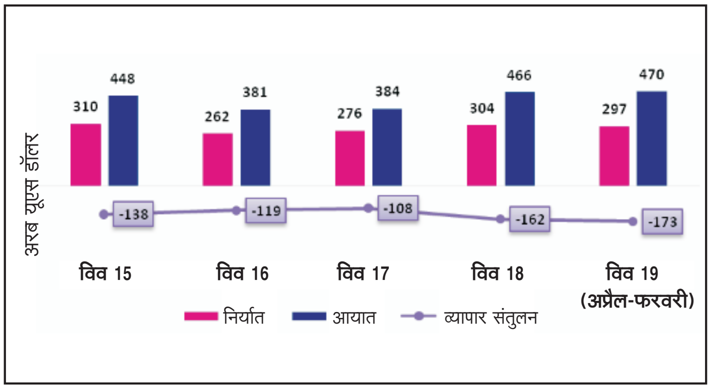

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सेवा व्यापार

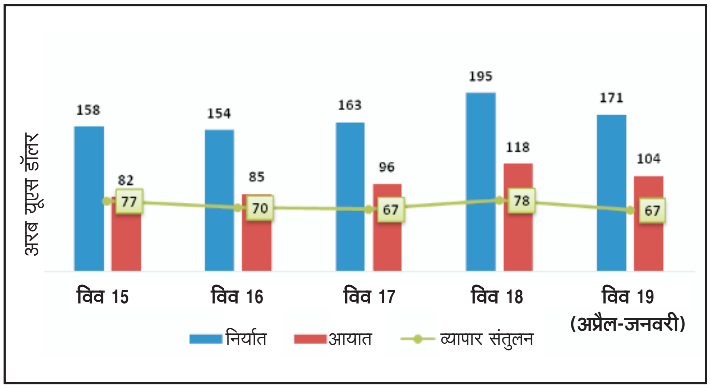

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह

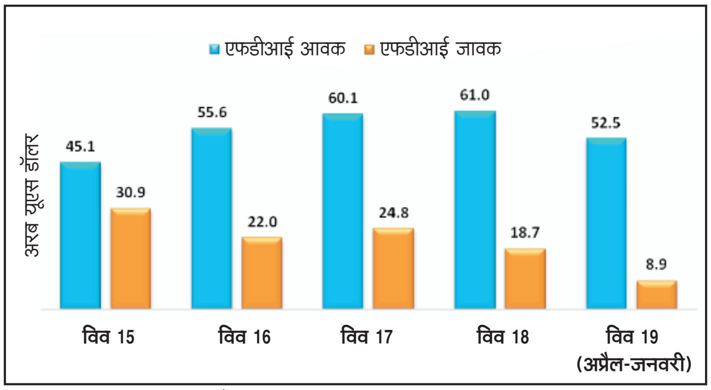

स्रोत : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई)

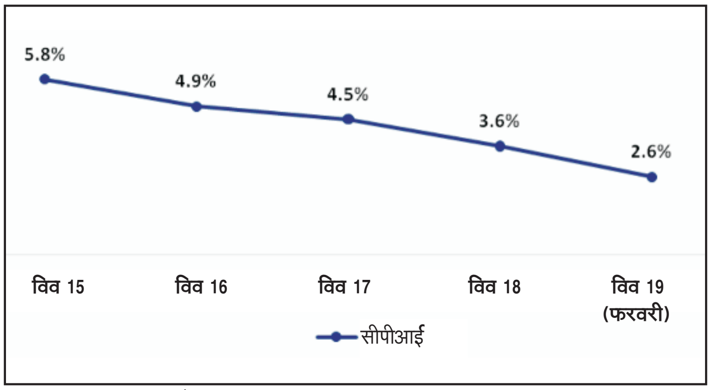

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चालू खाता घाटा

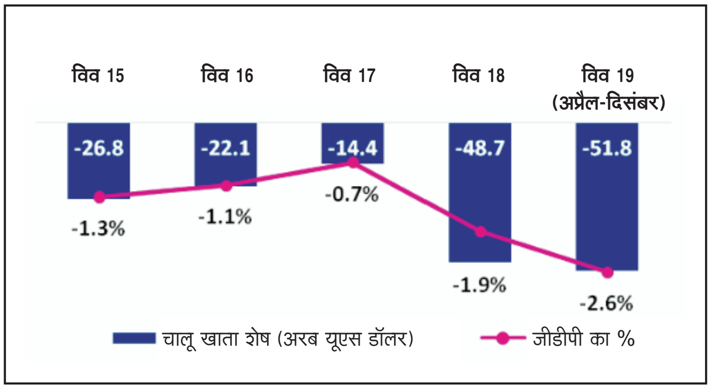

स्रोत : आरबीआई

क्षेत्रवार उत्पादन

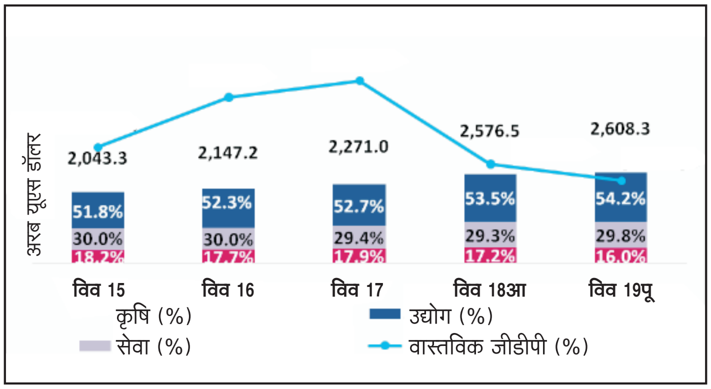

नोट : आ - आकलन, पू - पूर्वानुमान

स्रोत : आईआईएफ एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

व्यापार और साझेदारी अवसर

व्यापार अवसर

रेशम उत्पादन

एक सूक्ष्म उद्यम, जो हैंडलूम पर सिल्क की साड़ियां, दुपट्टे, सलवार-सूट, फैब्रिक और ड्रेस मैटीरियल बनाता है। इसमें 70 से अधिक बुनकर काम करते हैं। इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग से हैं।

आंवला

कुछ प्रोफेशनलों ने उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन के क्षेत्र में गरीबों को एक निश्चित आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से मिलकर 1977 में एक गैर-लाभकारी विकास संगठन के रूप में शुरुआत की।

लैकवेरयर

ग्रामीण दस्तकारों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के ग्रामीण और शहरी हस्तशिल्प क्षेत्र में काम करने वाले दस्तकारों के उत्थान की दिशा में काम करने वाला एक गैर लाभकारी संगठन। इस संगठन से करीब 5000 दस्तकारों को लाभ मिला है।

पिट लूम उत्पाद

पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में 12 गांवों के 200 से ज्यादा बुनकरों के साथ उनके कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था। ये बुनकर पिट लूम उत्पाद बनाते हैं, जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकते हैं।

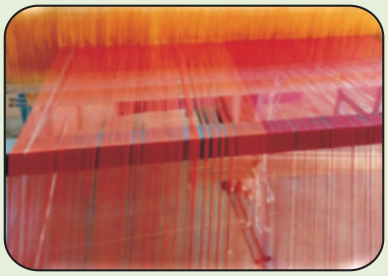

कौना वस्तुएं

प्लास्टिक की वस्तुओं के विकल्प के रूप में कौना घास से बने हस्तशिल्प उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम करने वाली सोसायटी। कौना उत्पाद सुंदर, मजबूत और 100% बायो-डीग्रेडेबल हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

तसर सिल्क

झारखंड स्थित कंपनी, तसर सिल्क धागे बनाती है। यह धागा उत्कृष्ट स्टोल, स्कार्फ, साड़ी और फैब्रिक बनाने के काम में आता है तथा जिसे भारत और दुनियाभर में साझेदारों के जरिए बेचा जाता है।

साझेदारी अवसर

परियोजना अवसर

(I) म्यांमार सरकार को सिंचाई और विकास परियोजना के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) से वित्तपोषण मिला है। म्यांमार सरकार इस निधि के कुछ अंश को कृषि विकास ईकाई के लिए परामर्शी सेवाओं के कॉन्ट्रैक्ट पैकेज के अंतर्गत भुगतान के लिए इस्तेमाल करना चाहती है।

(II) म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्रालय ने टेलीकॉम क्षेत्र की सुधार परियोजना के अंतर्गत मोबाइल नेटवर्क हेतु सेवा की टेस्ट क्वालिटी और बेंचमार्किंग टेस्ट सिस्टम के लिए पात्र फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। सरकार की यह पहल विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के अंतर्गत है। आरएफक्यू प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल, 2019 को सुबह 10.30 बजे तक है। (म्यांमार स्टैंडर्ड टाइम)

इच्छुक पार्टियां हमारी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार संपर्क कर सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए : फोन : 2217 2600 एक्सटेंशन : 2822 / 2737; फैक्स : 2218 8268. ईमेल : mas@eximbankindia.in